



एससी/एसटी एक्ट: सर्वोच्च न्यायालय

प्रलिस के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, एससी/एसटी (अत्याचार नविरण) कानून 1989 के प्रावधान

मेन्स के लिये:

'वशेष कानूनों' से संबन्धित आपराधिक मामलों को रद्द करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने एक फैसले का अवलोकन करते हुए पाया कशीरष अदालत और उच्च न्यायालयों के पास एससी/एसटी अधिनियम सहित वभिन्न 'वशेष कानूनों' के तहत दायर आपराधिक मामलों को रद्द करने की शक्ति है।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार नविरण) अधिनियम, 1989 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के पास [संवधान के अनुच्छेद 142](#) या [उच्च न्यायालय के आपराधिक प्रक्रिया संहिता](#) की धारा 482 के तहत नहित शक्तियाँ हैं।

प्रमुख बडि

- 'वशेष कानून' के तहत मामलों को रद्द करने की स्थिति:
 - जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वचिराधीन अपराध, भले ही एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आता है, प्राथमिक रूप से नजिी या दीवानी प्रकृति का है, या जहाँ कथित अपराध पीडित की जाती के आधार पर नहीं कथिा गया है, या कानूनी कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिये अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
 - जब दोनों पक्षों के बीच [समझौता/नपिटान के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर वचिर](#) करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अंतर्नहिति उद्देश्य का उल्लंघन नहीं कथिा जाएगा या कम नहीं कथिा जाएगा, भले [ईधविादति अपराध के लिये दंडति](#) न कथिा जाए।
- अनुच्छेद 142:
 - **प्रचिय:** यह सर्वोच्च न्यायालय को वविकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार कषेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारति कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबति कसिी भी मामले या मामले में पूरण न्याय करने के लिये आवश्यक हो।
 - **रचनात्मक अनुप्रयोग:** अनुच्छेद 142 के विकास के प्रारंभिक वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने समाज के वभिन्न वंचति वर्गों को पूरण न्याय दलाने या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लिये सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने [यूनयिन कारबाइड मामले](#) को भी अनुच्छेद 142 से संबन्धित बताया था। यह मामला भोपाल गैस त्रासदी के पीडितों से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को संसद या राज्यों की वधिनसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर रखते हुए कहा कि पूरण न्याय करने के लिये यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भी समाप्त कर सकता है।
 - हालाँकि [सर्वोच्च न्यायालय 'बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ'](#) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि [अनुच्छेद 142 का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतस्थापति करने के लिये नहीं, बल्कि एक वकिल्प के तौर पर कथिा जा सकता है।](#)
 - **न्यायकि अतरिक के मामले:** हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई नरिणय दथिे हैं जनिमें उसने उन कषेत्रों में प्रवेश कथिा है जो लंबे समय से न्यायपालिका के लिये 'शक्तियों के पृथक्करण' के सदिधांत के कारण नषिदिध थे, जो कि [संवधान की मूल संरचना का हसिंसा](#) हैं। उदाहरण :
 - **राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की बकिरी पर प्रतबिंध:** केंद्र सरकार द्वारा अधसूचना में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के कनारे शराब की दुकानों पर प्रतबिंध लगाने की बात कही गई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने [अनुच्छेद 142 को लागू करके](#) राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी पर प्रतबिंध लगा दथिा।
- **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482:**
 - यह धारा [उच्च न्यायालय को न्याय सुनशिति करने के लिये कोई भी आदेश पारति](#) करने की अनुमतति देती है। यह अदालत को नचिली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने या FIR रद्द करने की शक्ति भी देता है।

■ एससी/एसटी अधिनियम:

- एससी/एसटी अधिनियम 1989 को अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात समुदायों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिये संसद द्वारा अधिनियम का एक अधिनियम है।
- यह अधिनियम नरिशाजनक वास्तविकता को भी संदर्भित करती है क्योंकि कई उपाय करने के बावजूद अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजात उच्च जातियों के हाथों विभिन्न अत्याचारों के अधीन हैं।
- अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) तथा 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम किये गया है, जिसमें सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य हैं। यह कमजोर समुदायों के सदस्यों के साथ-साथ जाति आधारित अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करता है।
- अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजात संशोधन अधिनियम (2018) में प्रारंभिक जाँच ज़रूरी नहीं है और अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात पर अत्याचार के मामलों में FIR दर्ज करने के लिये जाँच अधिकारियों को अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-on-sc-st-act>